जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 358 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरुवार 31 अक्टूबर, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

कमला हैरिस की लीड कम होने से बेचैन हैं डैमोक्रैटिक पार्टी के रणनीतिकार

डैमोक्रैटिक पार्टी के नेताओं ने नई रणनीति पर विचार मंथन शुरू किया

- नई रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाना, समर्थकों को वोट देने के लिए प्रेरित करना, फोन पर और घर-घर जाकर प्रचार करना शामिल है।
- काफी हद तक दारोमदार उन वोटर्स पर है जिन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। हैरिस की पार्टी के नेता ऐसी नीति पर काम कर रहे हैं, ताकि, इन वोटर्स को अपनी तरफ किया जा सके।
- ट्रम्प की निरन्तर बढ़ती लीड का कारण यह है कि जनता अर्थव्यवस्था, रोजगार व इमिग्रेशन पर ट्रम्प की नीति को बेहतर मान रही है। हालांकि हैरिस कैपिटल रॉयट का मुद्दा उठा कर ट्रम्प को लोकतंत्र विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ राज्यों में ट्रम्प व हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है और ये राज्य ही विजेता का निर्धारण करेंगे।

-सुकुमार शाह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रम्प पर कमला हैरिस की बढ़त कम हो गई है। हाल ही में रॉयटर्स/इप्सॉस के पोल में पता चला है कि उनकी बढ़त मात्र एक प्रतिशत ही रह गई है। तीन दिन चला यह पोल रविवार को खत्म हुआ जिसमें दोनों नेता लगभग बराबरी पर रहे। ज्ञातव्य है कि 5 नवम्बर को यहां चुनाव होना है। ट्रम्प पर कमला हैरिस की बढ़त कम होने से जाहिर है कि डैमोक्रैटिक पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। जीत की संभावना बढ़ाने के लिए पार्टी नेताओं ने कई नीतिगत कदम उठाए हैं जैसे जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाना ताकि उनके समर्थक वोट देने आगे आएं। इसमें फोन पर प्रचार, घर-घर जाना और जनाधार मजबूत करने के लिए इवैंट्स कराना।

प्रमुख मतदाताओं को चिंताओं के समाधान के लिए संदेश दिया जाए, खासकर उन मसलों पर जिन पर ट्रम्प को बढ़त प्राप्त है जैसे अर्थव्यवस्था और इम्मिग्रेशन आदि। जिन मसलों पर हैरिस मजबूत हैं उन्हें उभारना होगा ट्रम्प की नीतियों से उनकी तुलना करनी होगी ताकि उन वोटर्स को अपनी तरफ किया जा सके जिन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

अब फोकस उन राज्यों पर हैं जहां असली मुकाबला है यहां प्रचार तेज करना होगा। संसाधनों को सक्रिय कर इन क्षेत्रों में हाइप्रोफाइल नेताओं को तैनात करना होगा जिससे डैमोक्रेटिक पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हैरिस ने युवा, महिलाओं व अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंच बनाई है जो उनकी सफलता के लिए जरुरी है, इन समूहों से सम्बंधित कदम उठाने से मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। आइडिया है कि वोटर्स के साथ बात कर उनकी समस्याओं को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए।

स्थानीय एडवोकेसी ग्रुप्स के साथ मिलकर सम्पर्क का दायरा बढ़ाने और समुदायों का भरोसा जीतना प्रमुख रणनीति होगा। कड़ी टक्कर को देखते हुए प्रत्याशियों की अपने समर्थकों को वोट में बदलने की क्षमता ही नतीजे निर्धारित करेगी। वर्ष 2020 के चुनाव से इस सदी का सर्वाधिक मतदान हुआ था। अमेरिका के दो तिहाई वयस्कों ने वोट डाला था।

वर्तमान चुनाव में 89 प्रतिशत डैमोक्रेट्स है और 93 प्रतिशत रजिस्टर्ड रिपब्लिकन्स ने मतदान करने का यकीन दिलाया है इसका अर्थ है कि वर्ष 2020 की तुलना में इस बार ज्यादा उत्साह है।

नवीन सर्वे में हैरिस ने ट्रम्प पर एक पॉइन्ट की बढ़त बनाई है। हालांकि जबसे हैरिस चुनावों में उतरी हैं वे लगातार ट्रम्प पर बढ़त बनाए हुए हैं। अक्टूबर में हुए पोल में उन्हें 2 पॉइन्ट की बढ़त मिली थी। पर इससे एक बात साफ उभरी थी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

25.75 लाख रुपए का मोटर दुर्घटना क्लेम खारिज

जयपुर, 30 अक्टूबर। मोटर दुर्घटना मामलों की विशेष अदालत, महानगर प्रथम ने 25.75 लाख रुपए का क्लेम खारिज करते हुए कहा कि मामले में यह साबित नहीं है कि बीमित वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना की है। अदालत ने यह आदेश विष्णु कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि बीमित वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन चला कर दुर्घटना की।

मामले से जुड़े अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के खिलाफ यह याचिका पेश की है। जिसमें कहा गया कि 21 मई, 2017 को वह प्रकाश चन्द्र के साथ मोटरसाइकिल पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अवकाश की सूचना

दीपावली के उपलक्ष्य में राष्ट्रदूत कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर व 1 नवम्बर 2024 को अवकाश रहेगा। अगला अंक 3 नवम्बर को प्रकाशित होगा। - प्रबंध सम्पादक

'कैनडा में अलगाववादी सिख हरदीप सिंह की हत्या के लिए अमित शाह ने स्वीकृति दी थी'

- यह खबर वॉशिंगटन पोस्ट में एक कैनेडियन अधिकारी के हवाले से छपी थी। कैनडा के डिप्टी विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने स्वीकार किया, कि वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के वो ही सूत्र हैं।
- भारत सरकार ने खबर की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, "क्योंकि कैनडा के प्रधानमंत्री अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं, और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, भारत सरकार उनके हर वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं समझती।
- कैनडा ने भारत से यह भी कहा है कि वे गैंगस्टर लॉरैंस विश्नोई पर नियंत्रण रखें, जिससे वह कैनडा में अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सके।
- अभी हाल ही में पंजाब पुलिस ने, एक उच्च पुलिस अधिकारी के ऑफिस को एक टी.वी. स्टूडियो में परिवर्तित करके लॉरैंस विश्नोई को अपना इन्टरव्यू देने की सुविधा दी थी।

-श्री नन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। भारत-कैनडा विवाद और भी बढ़ गया है। ओटावा द्वारा गृहमंत्री अमित शाह पर ऑन-रिकॉर्ड आरोप लगाने तक की नौबत आ गई है। ओटावा ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने कैनडा सिक्ख अलगाववादियों के खिलाफ निगरानी तथा हिंसा के अधिकार दे दिये हैं। कैनडा के उप विदेश मंत्री डेविड मैरिसन ने वॉशिंगटन पोस्ट के उस लेख के आधार पर, मंगलवार को इस बात की पुष्टि की, जिसने इस माह के प्रारम्भ में सबसे पहले अमित शाह के खिलाफ आरोपों की रिपोर्टिंग की थी। भारत सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। एक भारतीय अधिकारी ने कहा, "सिर्फ इसलिये, कि कैनडा में इस समय एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिये किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भारत के गृहमंत्री इस बयान को तवज्जोह देंगे, जिसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाना चाहिये, क्योंकि यह बयान तिरस्कार रख घृणा का ही हकदार हैं।"

इसी बीच, कैनडा ने भारत से यह कहा भी है कि वह जेल में बन्द गैंगस्टर लॉरैंस विश्नोई को कैनडा में और कारनामे करने से रोके। प्रसंगवश बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुये कहा कि पुलिस ने इस गैंगस्टर को, अपने हाल ही के टेलीविजन इन्टरव्यू के लिये स्टूडियों के रूप में, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के दफ्तर को काम में लेने दिया। न्यायमूर्ति अनुपिन्दर सिंह तथा लपिता बनर्जी की बैंच ने कहा, "पुलिस अधिकारियों इस क्रिमिनल को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम में लेने की अनुमति दे दी तथा इन्टरव्यू के आयोजन के लिये उसे स्टूडियो जैसी सुविधा उपलब्ध कराई। ऐसे काम से अपराध का महिमा मंडन होता है तथा ऐसी सम्भावना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पराली जलाने से ज्यादा प्रदूषण तो वाहनों से हो रहा है'

कांग्रेस ने हैल्थ एण्ड क्लाइमेट चेंज पर लैन्सैट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा

- कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पराली जलाने को प्रदूषण का बड़ा कारण बताया जाता है पर लैन्सैट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 से 2024 के बीच पराली जलाने के मामले 51 प्रतिशत कम हो गए हैं और दिल्ली का प्रदूषण बढ़ने में पराली जलाने का योगदान मात्र 0.92 प्रतिशत ही है।
- जयराम रमेश ने कहा, वायु प्रदूषण भारत में जनस्वास्थ्य की एक प्रमुख चुनौती है और इससे निपटने के लिए हमें भारी बदलाव करने होगें। अक्षय ऊर्जा, इलैक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक यातायात को प्राथमिकता देनी होगी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि, दॅ लैन्सैट काउन्टडाउन ऑन हैल्थ एण्ड क्लाइमेट चेंज की नई रिपोर्ट ने भारत में वायु प्रदूषण के बारे में चिंताजनक निष्कर्ष दिए हैं।

– सन् 2021 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में कुल 16 लाख मौतें हुईं।

– इनमें से 38 प्रतिशत मौतों में कोयला तथा लिक्विड गैस जैसे फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) की भूमिका थी।

– सन् 2022 में भारत ने दुनिया के उपभोग आधारित पी.एम. 2.5 उत्सर्जन में 15.8 प्रतिशत और दुनिया के कुल वायु प्रदूषण में 16.9 प्रतिशत का योगदान दिया। दुनिया के उत्पादन आधारित पी.एम. 2.5 (जहरीली हवा में मौजूद बारीक कण) उत्सर्जन में यह सबसे बड़ा योगदान है। ये प्रदूषण कण 2.5 माक्रोमीटर से भी कम होते हैं और सीधे फेफ ड़ों में प्रवेश कर सकते है।

जयराम ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों ने हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का उदाहरण पेश किया है।

– 16 अक्टूबर तथा 22 अक्टूबर 2024 के बीच, पी.एम. 2.5 का औसत 104 यूजी/एम3 से बढ़कर चिंताजनक 168 यूजी/एम3 तक पहुँच गया।

– तथापि पराली जलाना, जिस पर लम्बे समय से दिल्ली के वायु-प्रदूषण को लेकर दोषारोपण होता रहा है, नासा के "विज़िबल इन्फ्रारैड इमेजिंग रेडियोमीटर स्वीट (वी.आई.आई.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लद्दाख में सेना हटने की प्रक्रिया पूरी हुई

नई दिल्ली/लद्दाख, 30 अक्टूबर। पूर्वी लद्दाख सीमा पर देपसांग और डेमचोक पॉइंट से डिसएंगेजमैंट (सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया) पूरा हो चुका है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, दोनों पॉइंट से भारत-चीन की सेनाओं की टुकड़ी की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है। गुरुवार को दीपावली के दिन सैनिकों में मिठाइयां बांटी जाएंगी। इसके बाद जल्द ही इन दोनों पॉइंट पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग शुरू करेगी। इस दौरान लोकल कमांडर स्तर की बातचीत चलती रहेगी।

- भारत व चीन की सेनायें अप्रेल 2020 से पहले की स्थिति में लौटीं।

इससे पहले एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि भारत और चीन 28-29 अक्टूबर तक एल.ए.सी. पर सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

देपसांग और डेमचोक से पीछे हटने की जानकारी 18 अक्टूबर को सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि यहां से दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहली की स्थिति में वापस लौटेंगी। साथ ही उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी, जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थीं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजनैतिक अनिश्चितता से जूझ रहा है जापान

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह कदापि अच्छी स्थिति नहीं है

- प्रधानमंत्री शिगेरु इशीबा ने मध्यावधि चुनाव का जो दांव खेला उसमें उन्हें विफलता मिली। लम्बे समय से सत्तारुढ़ पार्टी, लिबरल डैमाक्रैटिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि, शिगेरु ने छोटे दलों से गठबंधन कर बहुमत जुटा लिया है।
- बहुमत भले ही मिल गया हो पर जमीनी स्तर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं।
- लम्बे समय से "डिफ्लेशन" (मांग और कीमतों में कमी) से जूझ रहे जापान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई है। शिगेरु ने "डिफ्लेशन" को दूर करने का प्रयास किया, जिससे कीमतें बढ़ीं और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट भी बढ़ी।
- लेकिन जापान की जनता को मूल्य वृद्धि रास नहीं आई उन्हें "डिफ्लेशन" की आदत हो गई है। महंगाई बढ़ने पर जापान की जनता की नाराज़गी चुनाव नतीजों में दिखी है।

-अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर। गत रविवार जापान के चुनाव नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अच्छा अर्थशास्त्र अक्सर राजनैतिक लाभ नहीं देता है। पर इसका अर्थ यह है नहीं है कि खराब अर्थशास्त्र राजनैतिक रूप से फायदेमंद होता है।

इस सोमवार चुनाव नतीजे स्पष्ट हो गए। यह साफ था कि प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा संकट में थे। उन्होंने मध्यावधि चुनाव घोषित कर एक दांव खेला उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें ज्यादा ठोस बहुमत मिलेगा।

लेकिन नतीजे उलट आए लम्बे समय तक शासन करने वाली लिबरल डैमोक्रेटिक पार्टी को बहुत अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। बहुमत के लिए 233 सीटों की जरूरत थी पर इसे 191 ही मिली जबकि पहले इसके पास 247 सीटें थी। अब छोटे सहयोगी कोमेईतो की बदौलत गठबंधन के पास 247 सीटें हो पाई हैं।

एल.डी.पी. के सामने कई मजबूरियां हैं इसे बहुमत जुटाने के लिए कई छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ा। नम्बर भले ही जुट गया हो पर जमीनी स्तर पर स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। जापान कई वर्षों से अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार से जूझ रहा है। इसका पहला लक्षण है डिफ्लेशन।

डिफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिससे निपटना इनफ्लेशन की तुलना में कठिन है। जब एक लम्बे समय तक कीमतें गिरती रहती हैं तो ऐसी मानसिकता उत्पन्न होती है जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के खिलाफ होती है।

तब उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं पर धन खर्च नहीं करते हैं। वे यह सोचते हैं कि निकट भविष्य में यह असफल हो जाएगी। इस प्रकार खर्च कम हो जाता है।

तीन दशकों से जापान इसी स्थिति का सामना कर रहा है और अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता तक ग्रोथ नहीं कर पाई है। जापान के इकोनॉमिक मैनेजर्स ने हर तरीका आजमा लिया है। बैंक ऑफ जापान ने ऐतिहासिक रूप से भारी कमी भी की थी।

यही नहीं सैंट्रल बैंक ने नैगटिव इंट्रैस्ट रेट्स भी शुरू की थी जो कि सैंट्रल बैंकिंग के इतिहास में अप्रत्याशित था। इसका अर्थ था कि अगर उसने अपनी बचत बैंक में जमा की तो उसमें कमी होगी, बैंक के पैसा रखने पर ब्याज देने की बजाय वे थोड़ी ही राशि वसूलते थे।

स्थिति हाल ही में बदली थी। बैंक ऑफ जापान ने दो प्रतिशत का इनफ्लेशन टारगैट रखा था जो लगभग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शौचालय में यात्री पाये गये तो ट्रेन नहीं चलेगी

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष दीपावली एवं छठ पर्व पर देश के पूर्वी भाग की ओर यात्रा करने वाले साधारण श्रेणी के यात्रियों को गरिमापूर्ण मानवीय दशा में यात्रा सुलभ कराने के लिए पहली बार अनेक पहलें कीं हैं।

रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, साधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए इस साल 7296 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनायी गयी है। ये गाड़ियां एक अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच मांग को देखते हुए चलायी जाएंगी।

- भारतीय रेल्वे ने यात्रियों की गरिमा व सुरक्षा के लिये नये इन्तजाम किये।

सूत्रों के अनुसार, इस साल के त्योहारी सीज़न में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड की ओर लगभग एक करोड़ लोग रोज़ाना यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से 22 से 23 लाख आरक्षित श्रेणियों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैनडा ने अचानक इतना भारत विरोधी रवैया क्यों अपनाया है?

क्या कैनडा, अमेरिका के "प्रॉक्सी" के रूप में काम कर रहा है

- अमेरिका, भारत की पुतिन से दोस्ती व रूस से नजदीकियां बढ़ने से ज्यादा खुश नहीं है, और भारत को रूस से दूर करने के लिये भारत को कई सुविधाएं व रियायतें देने का लालच दिया है। पर भारत ने बदस्तूर रूस से मित्रता व नजदीकी लगातार बढ़ाई ही है, कम नहीं की, जैसा कि रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में देखा गया।
- दूसरी ओर भारत व चीन ने भी सीमा पर तनाव कम करने के लिए एग्रीमैंट (समझौता) भी किया है।
- इस तरह भारत का रूस-चीन धुरि के करीब जाना भी अमेरिका को रास नहीं आ रहा।
- अमेरिका भारत को अपनी "नाखुशी" जताने के लिए कैनडा का उपयोग कर रहा है, और इसीलिए कैनडा ने पहले निज्जर की हत्या में भारत के गृहमंत्री को घसीटा, और फिर कैनडा की संसद के ग्राउण्ड्स पर अचानक दीवाली का प्रोग्राम रद्द करने का बेवजह निर्णय लिया है। कैनडा, अमेरिका का प्रॉक्सी बनकर भारत को तंग व असहज करने का प्रयास कर रहा है।

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। न्यूज़ एजेन्सी ब्लूमबर्ग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कैनडा के एक अधिकारी ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने, एक सिख अलगाववादी के लिए "मर्डर प्लॉट" को "अधिकृत" किया था।

एजेन्सी ने अपनी रिपोर्ट में कैनडा के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि अमित शाह ने हमले के लिए हरी झंडी दी। इसके खुलासे के बाद यह विवाद एक नए ही स्तर पर पहुंच गया है।

इससे पहले, कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने आरोप लगाया था कि कैनडा के बड़े सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय अधिकारी लिप्त थे। इस आरोप से दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद, कैनडा के प्रधानमंत्री अपने आरोपों को प्रमाणित करने वाले ठोस सबूत नहीं दे पाये थे।

अब, कैनडा के अधिकारी द्वारा लगाये गये ताजा आरोप के दावे दोनों देशों के बीच के उस विवाद को आग में फिर से घी का काम कर रहे हैं। यह समाचार अन्य किसी नये संगठन द्वारा नहीं लाया गया है।

इसके बाद की रिपोर्टों के अनुसार, कैनडा ने यह जानकारी अमेरिका को दी थी तथा अमेरिका ने भारत से अनुरोध किया था कि वह संबंधित जांच में कैनडा के साथ सहयोग करे। भारत ने जोरदार तरीके से इन आरोपों का खंडन किया था तथा कैनडा सरकार से ठोस सबूत देने के लिए कह दिया था।

अब यह विवाद एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है क्योंकि अब लगाये गये आरोपों में केन्द्रीय गृह मंत्री की लिप्तता बताई गई है। एक बार फिर, आरोपों को प्रमाणित करने वाले कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इस बीच, एक अन्य विवाद और पैदा हो गया। दरअसल, कैनेडियन संसद में विपक्ष के नेता पियरे पोइलीवर ने "दिवाली" त्यौहार रद्द कर दिया है। त्यौहार के आयोजकों को इसे रद्द करने के कोई कारण नहीं बताये गये हैं। उन्हें इस त्यौहार को रद्द करने की सिर्फ सूचना दी गई है।

भारतीय समुदाय ने अचानक किए इस निरस्तीकरण के बारे अधिकारियों को कड़ा प्रतिवेदन दिया गया है तथा मांग की गई है कि प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो इसके लिए माफी मांगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो कैनडा के राजनैतिक वर्ग जान-बूझकर भारत विरोधी वक्तव्यों और कार्यवाहियों से भड़का रहे हैं।

हालांकि यह अभी पूरी तरह निश्चित एवं स्पष्ट नहीं है कि कैनडा ने अचानक यह भारत-विरोधी रुख आखिर क्यों इख्तियार किया है। चूंकि प्रायः यह माना जाता है कि कैनडा, अमेरिका के इशारे पर काम करता है, अतः हो सकता है कि कैनडा के ये कदम अमेरिका के संकेत पर तथा अमेरिकन प्रशासन के कुछ वर्गों के आदेश पर किए जा रहे हों। दरअसल, अमेरिका इस बात से बहुत परेशान है कि भारत, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए है। सर्वविदित है कि पुतिन के नेतृत्व में रूस पर पश्चिमी गठबंधन के पहले दुश्मन का ठप्पा लगा हुआ है।

अमेरिका ने भारत को रूसी खेमे से दूर करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना ने ओ.बी. सी. जातीय जनगणना की मांग की

तेलंगाना, 30 अक्टूबर। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने एक मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से मांग की कि अगले साल प्रस्तावित जनगणना में ओ.बी.सी. जातीय जनगणना को शामिल किया जाए।

- राज्य सरकार ने अगले साल प्रस्तावित जनगणना में ओ.बी.सी. जातीय जनगणना शामिल करने की केन्द्र सरकार से मांग की है।

बुधवार को कांग्रेस की हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और अन्य नेता मौजूद रहे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टी.पी.सी.सी.) के अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किए गए व्यापक सामाजिक, शैक्षिणक, आर्थिक, रोजगार और राजनीतिक एवं जातीय सर्वेक्षण पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)